

## एनबीएफसी विनियमन – भविष्य पर विचार \*

एम. राजेश्वर राव

डॉ. चरण सिंह, श्री दीपक सूद, श्री रमेश अय्यर, श्री विनीत अग्रवाल, श्री एस रमन, श्री सुनील कनोरिया, श्री रमन अग्रवाल, देवियो और सज्जनों,

"वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और निरंतरता" के थीम पर गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर राष्ट्रीय ई-शिखर सम्मेलन को संबोधित करने हेतु एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एशोचैम) के इस उदार आमंत्रण के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

इस समय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। हाल में कुछ बड़े एनबीएफसी की विफलताएं, क्षेत्र में तरलता (चलनिधी) का घोर दबाव और इसके चलते होने वाली वित्तीय स्थिरता की चिंताओं ने एनबीएफसी विनियमों पर ध्यान खींचा है। मैंने महसूस किया कि एनबीएफसी सेक्टर में हो रहे नवोन्मेषी परिवर्तनों और रिजर्व बैंक की विनियामक प्रतिक्रिया पर कुछ चर्चा का यह उपयुक्त समय है। विनियामक ध्यान की दिशा और भविष्य में एनबीएफसी विनियमों के संभावित आकार का जायजा लेना प्रासंगिक होगा। इस विश्लेषण का उद्देश्य विषय पर चर्चा और बहस को उद्बलित करना है।

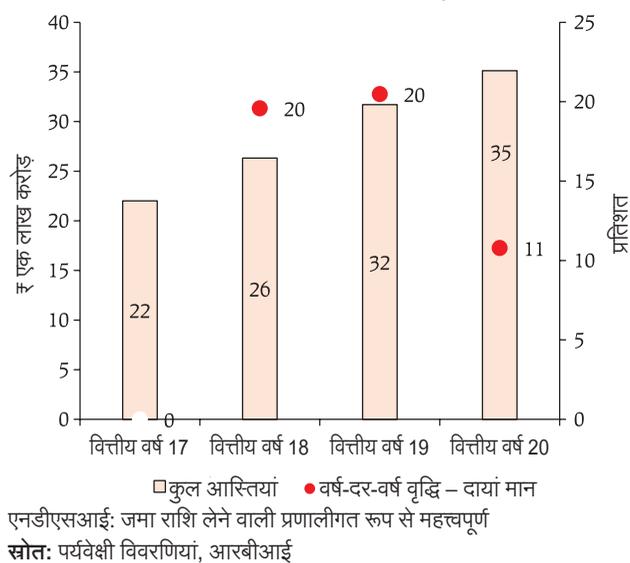
### एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि और विवेक की आवश्यकता

अपने आकार व संचालन की विविधता की दृष्टि से एनबीएफसी ने एक लंबी यात्रा तय की है। वे अब बैंकों से अल्पतर-सेवित ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में वित्तीय सेवाओं को आखिरी मील तक उपलब्ध कराके वित्तीय मध्यस्थता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में

अहम भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों में, यह वर्ग तेजी से बढ़ा है, और कुछेक बड़े एनबीएफसी आकार में कतिपय प्राइवेट सेक्टर बैंकों के बराबर हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई गैर-पारंपरिक खिलाड़ियों का प्रवेश भी हुआ है जो तकनीक आधारित नवोन्मेषी कारोबारी मॉडल अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं।

31 मार्च, 2009 और 31 मार्च, 2019 के बीच, एनबीएफसी की कुल आस्तियां 18.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि (कम्पाउंडेड) वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ीं, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की बैलेंस शीट 10.7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ीं। नतीजतन, एनबीएफसी की समग्र बैलेंस शीट का आकार इसी अवधि के दौरान एससीबी की समग्र बैलेंस शीट आकार के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 18.6 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ (एबसोल्यूट टर्म्स) में, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एनबीएफसीसेक्टर [हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज (एचएफसी) सहित] का एसेट साइज (आस्ति आकार) ₹51.47 लाख करोड़<sup>3</sup> है। मार्च 2020 के अंत में, वित्तीय

**चार्ट 1: एनबीएफसी क्षेत्र का आकार (जमा राशि लेने वाली और एनडीएसआई)**



<sup>2</sup> भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (2010 और 2019)

<sup>3</sup> एनबीएफसीज की एसेट साइज (जमा राशि लेने वाली, एनडीएसआई, नॉन-एनडीएसआई) - ₹37,38,162 करोड़। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) का आस्ति आकार (एसेट साइज) - ₹14.09 लाख करोड़।

<sup>4</sup> वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, जुलाई 2020।

\* श्री एम राजेश्वर राव, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। एसोचैम द्वारा 6 नवंबर, 2020 को आयोजित 'नेशनल ई-समिट ऑन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज' में दिया गया भाषण। मनोरंजन मिश्र, श्री चंदन कुमार और श्री प्रदीप कुमार से प्राप्त इनपुट के लिए आभार।

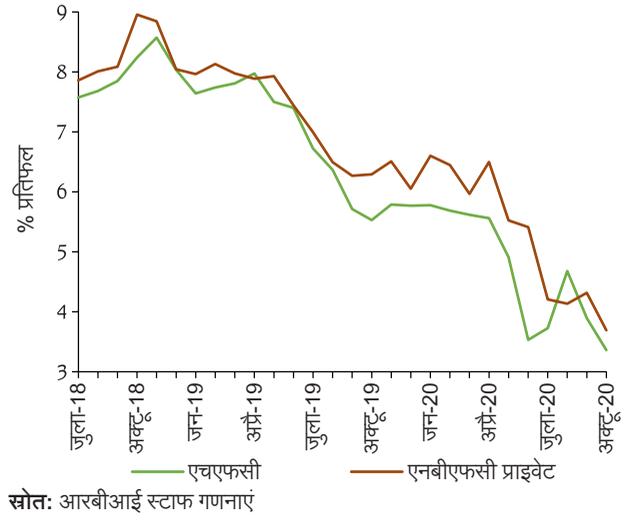
प्रणाली<sup>4</sup> से निधियों के सबसे बड़े निवल उधारकर्ता एनबीएफसी रहे हैं, जिनमें से आधी से अधिक निधियां एससीबी से थीं, जिसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनियां-म्युचुअल फंड्स (एएमसी-एमएफ) और बीमा कंपनियां थीं। जैसे-जैसे वित्तीय मध्यस्थता बदली है, वैसे-वैसे अंतरसंबद्धता बढ़ी है। कई एनबीएफसी अब धन और आपातकालीन तरलता /चलनिधि (लिक्विडिटी) जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर हैं। इसलिए, केवल बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों को समझना और उनसे निपटना काफी नहीं। इस समय जरूरत है एनबीएफसी क्षेत्र की कमजोरियों समझने की और यह जानने की कि आघात कैसे या इस क्षेत्र से या की ओर संचरित होते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय क्षेत्र संस्थाओं के साथ इस क्षेत्र की अंतरसंबद्धताएं बैलेंस शीट के दोनों ओर हैं ओर उत्तरोत्तर जटिल। वैसे भी, वित्तीय बाजारों और हमारे जीवन पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव के पहले से ही अन्य वित्तीय मध्यस्थों की तरह एनबीएफसी भी प्रतिपक्ष, वित्त पोषण, बाजार और आस्ति संकेंद्रण जोखिमों के प्रति अधिकाधिक एक्सपोज्ड हैं।

### महामारी का प्रभाव

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफएचएल) की घटनाओं के बाद तरलता दबाव (लिक्विडिटी स्ट्रेस) के कारण, एनबीएफसी के लिए बाजार फंडिंग की स्थितियां मुश्किल हो गईं। अभिशासन के बेहतर मानकों और काम-काज के बेहतर तौर-तरीकों वाली एनबीएफसी जहाँ ठीक चलीं वहीं दूसरों को बाजार का प्रकोप झेलना पड़ा। छोटे एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान /माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई), जो आखिरी मील तक तक क्रेडिट वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वे भी प्रभावित हुए क्योंकि उनके धन (फंडिंग) के स्रोत सूख गए। रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति और चलनिधि उपायों द्वारा फंडिंग और लिक्विडिटी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए तेजी और अग्रसक्रियता से काम किया और इसके परिणामस्वरूप, सभी

**चार्ट 2: फंडिंग लागत: 3-माह वाणिज्यिक पत्र (सीपी) भारत औसत प्रतिफल**



रेटिंग श्रेणियों के लिए एनबीएफसी और एचएफसी के लिए धन की लागत काफी कम हो गई है (चार्ट-2)।

यह समझना अहम है कि कुछ एनबीएफसी जो चुनौतियां झेल रही हैं, वे उनकी अंतर्निहित कमजोरियों के चलते हैं। जैसे-जैसे वित्तीय बाजारों ने मजबूत / सुप्रबंधित और स्पष्टतः कमजोरियों से ग्रसित एनबीएफसी के बीच अंतर करना शुरू किया, बाजार अनुशासन का प्रभाव दिखने लगा - आस्ति-देयता विसंगति या आस्ति गुणवत्ता की समस्या वाली इकाइयों को बाजार तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। यह देखते हुए रिज़र्व बैंक ने, एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह लाने और क्षेत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता में सुधार के लिए कई नपे-तुले कदम उठाए।

### सारणी 1: एनबीएफसी क्षेत्र (जमाराशि लेने वाली और एनडीएसआई) की लाभप्रदता

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभप्रदता मानक	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020
निवल लाभ (₹ करोड़)	31,923	42,434	17,460	41,257
वार्षिकीकृत आरओए (%)	1.5	1.6	0.6	1.2
वार्षिकीकृत आरओई (%)	6.3	6.8	2.4	5.1

टिप्पणी: आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओई)।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

यह क्षेत्र जब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा था (जैसा कि नीचे दी गई सारणी (टेबल) -1 से देखा जा सकता है), कोविड -19 का प्रकोप और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण वित्तीय प्रणाली में भारी दबाव बना। पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुई थी, एनबीएफसी के अंतर्निहित व्यापार मॉडल के कारण उन पर असर अधिक हुआ, और उनकी लाभप्रदता पर बोझ पड़ा।

### विनियामक दृष्टिकोण

एनबीएफसी क्षेत्रके अंतर्गत आने वाली इकाइयों की बढ़ती जटिलता और वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व के अनुसार रिज़र्व बैंक ने अपने विनियामक दृष्टिकोणको ढाला है। तथापि एनबीएफसी विनियम के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात् ए) जमाकर्ताओं (जमा-स्वीकार करने वाली कंपनियों के मामले में) और ग्राहकों की सुरक्षा ; और बी) वित्तीय स्थिरता का संरक्षण। अलग-अलग समय पर इन उद्देश्यों के महत्व में परिवर्तन को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग नीतिगत साधनों का प्रयोग किया है। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हाल के वर्षों में एनबीएफसी विनियमन में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं।

इनमें से पाँच सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की संक्षिप्त जानकारी दे दूँ

- (i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्वामित्व-तटस्थ नियमों को प्राथमिकता देने के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार के स्वामित्व वाले एनबीएफसी मई 2018 से विवेकपूर्ण नियमन के दायरे में लाए गए हैं। यह देखते हुए कि पूरे एनबीएफसी क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक सरकारी स्वामित्व वाला है, मुख्यतः बुनियादी ढांचे की फाइनेंसिंग में, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
- (ii) दूसरा, तरलता (चलनीधि/लिक्विडिटी) दबाव के कारण कुछ एनबीएफसी द्वारा हाल में झेले गए उथल-पुथल को देखते हुए, ₹100 करोड़ से ऊपर की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए चलनिधि (तरलता) जोखिम प्रबंधन ढाँचा (फ्रेमवर्क) लागू कर एनबीएफसी

द्वारा तरलता जोखिम के अच्छे प्रबंधन के महत्व पर बल दिया गया है। सभी एनबीएफसी, चाहे वे किसी भी आकार के हों, इस फ्रेमवर्क को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देशों में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा प्रकाशित 'अच्छे चलनिधि (तरलता) जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों' पर जोर दिया गया है। ढाँचे में एनबीएफसी के बोर्ड्स से प्रत्याशित है कि तरलता जोखिम के प्रबंधन में एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे और अपने व्यावसायिक स्वरूप के लायक आंतरिक निगरानी के साधनों की व्यवस्था करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियमों ने बड़े एनबीएफसी के लिए सरलीकृत और उनके अनुरूप चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाया है। इसकी सहायता से बड़े एनबीएफसी 30 दिनों तक की अवधि के गंभीर चलनिधि दबाव वाले परिदृश्यों में भी नकदी के बहिर्गमन (ऑउटफ्लो) से प्रभावी ढंग से निपट सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (लिक्विड एसेट्स) बनाए रखने का एनबीएफसी के समग्र प्रतिफल पर असर होगा, लेकिन परिपक्वता / चलनिधि परिवर्तन के जो कार्य एनबीएफसी करते हैं, यह विनियमन उनसे संबंधित जोखिमों को कम करने की आवश्यकता के अनुरूप है।

- (iii) तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम फिनटेक आधारित उत्पादों की डिलीवरी से जुड़ा है। अब यह व्यापक मान्यता है कि बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र वित्तीय उत्पादों व सेवाओं में प्रयोग की उपजाऊ भूमि होगी। विनियमों ने इस दिशा में सहायक परिवेश बनाने की कोशिश की है उदाहरण के लिए, समकक्षीय उधार माध्यमों (पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) संबंधी दिशा-निर्देशों के समय से लाए जाने से इस वर्ग का सुव्यवस्थित विकास हो पाया जो विवेक के उच्च मानकों से संचालित है। विनियमों ने जोखिम कम किए हैं और व्यसाय के अवसरों के वैध विस्तार हेतु उपयुक्त माहौल बनाया है। खाता समूहक (एए) के अंतर्गत बनाया गया परितंत्र तकनीक-आधारित गतिविधियों

में अग्रसक्रिय विनियमन का एक और उदाहरण है। एए फ्रेमवर्क से ग्राहक की वित्तीय आस्तियों संबंधी सूचना के संरक्षित, सुरक्षित ढंग से और सहमति से शेयर किए जाने हेतु अपेक्षित फ्रेमवर्क शुरुआत हुई है। यहाँ ध्यान देने योग्य विनियामक पक्ष यह है कि खाता समूहक अपने यहाँ से गुजर रहे डेटा को स्टोर नहीं करता और न ही देखता है जिससे वित्तीय डेटा के कुप्रयोग/दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं होती। मैं यह भी रेखांकित करना चाहूँगा कि पंजीकृत एनबीएफसी को वित्तीय मध्यस्थता में पूर्णतः ऐप-आधारित होने की अनमति देने में रिज़र्व बैंक का रुख लचीला रहा है।

- (iv) रिज़र्व बैंक ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (सीआईसी) के लिए आनुपातिकता के सिद्धांतों के तहत नियामक ढांचे को संशोधित किया जिसमें संशोधित पारदर्शिता व खुलासों पर ध्यान दिया गया है। एक बड़ी एनबीएफसी - एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की विफलता से मिला सबक इस विनियामक नवीनीकरण का कारण बना। समूह स्तर पर बड़े समग्र लीवरेज और जटिल, बहुस्तरीय स्वामित्व वाली संरचनाएं वित्तीय अस्थिरता और कमजोरी के बीजों का पोषण करती पाई गई। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी स्तर पर जोखिम का समग्र दृष्टिकोण नहीं था। संशोधित नियामक ढांचा सीआईसी से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनियामक अंतराल को पाटने की कोशिश करता है।
- (v) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन को हाथ में लेना और एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद एचएफसी के नियामक ढांचे में परिवर्तन जारी किए गए हैं। विचार है कि एचएफसी को एनबीएफसी की एक श्रेणी माना जाए और एचएफसी को अपनी विशिष्ट विशेषताएं बनाए रखने देते हुए विनियमों का सामंजस्य स्थापित किया जाए और संशोधित विनियमों की ओर उनको क्रमिक रूप से इस तरह बढ़ने दिया जाए जो शेष वित्तीय क्षेत्र के लिए कम से कम उथल-पुथल वाला हो।

आकार और अंतर्संबद्धता बढ़ने के साथ, एनबीएफसी तेजी से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं और वित्तीय स्थिरता

पर अधिक ध्यान देने के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के विवेकपूर्ण नियम विकसित हुए हैं। तथापि, हम यह न भूलें कि अल्प-विनियमन-संरचना के चलते एनबीएफसी को लचीलेपन का लाभ मिला है। प्राथमिक रूप से यह लचीलापन बैंकों के मुकाबले एनबीएफसी को तुलनात्मक लाभ देता है, जिससे वे वित्तीय मध्यस्थता के अंतिम मील की सेवा कर पाते हैं। इसलिए, एनबीएफसी को अधिक सख्ती से विनियमित करने और उन्हें अपेक्षित लचीलापन देने की आवश्यकता के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। जब हम एनबीएफसी हेतु विनियमन के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो यह उसका आधार रहेगा।

## भविष्य

### आनुपातिकता सिद्धांत

एक दृष्टिकोण यह है कि आदर्शतः कोई भी विनियामक ढाँचा आनुपातिकता के सिद्धांत पर बनाया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय स्थिरता पर स्पष्ट प्रभाव डाल सकने वाले प्रणालीगत रूपसे महत्वपूर्ण एनबीएफसी से फैलने वाले जोखिम का निपटान भी तदनुसार होना चाहिए। अतः, महत्वपूर्ण बाह्य प्रभाव वाले एनबीएफसी, जिनका प्रणालीगत जोखिम में बड़ा योगदान है, की पहचान और उन पर उच्चतर स्तर का विनियमन आवश्यक है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि ऐसे एनबीएफसी हेतु विवेकसम्मत विनियामक ढाँचा बैंकों के तुल्य हो ताकि प्रणालीगत जोखिम की गंभीरता की एक हद के बाद ये एनबीएफसी वाणिज्य बैंकों में बदलने को प्रेरित हों अथवा वित्तीय व्यवस्था में अपने बाह्य प्रसार को घटाएं। इससे वित्तीय व्यवस्था स्वस्थ व सुदृढ़ बनेगी साथ ही, अधिकांश एनबीएफसी अल्प-विनियमन संरचना के तहत बनी रह सकेगी।

आनुपातिकता सिद्धांत के अंतर्गत उन इकाइयों पर ध्यान आवश्यक है जो प्रणालीगत रूप से न बेहद अहम हैं और न ही अपने आकार व जटिलता में बहुत छोटी हैं। बैंकों की तुलना में ये एनबीएफसी वर्तमान में विनियामक अंतरपणन का लाभ काफी अधिक ले रही हैं। विनियामक अंतरपणन के कारण समूह के रूप में, प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाने में इन इकाइयों का हाथ है; इसलिए विनियमों को तदनुसार फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है।

आनुपातिकता सिद्धांत की चर्चा में, मैं माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के विनियमन का भी उल्लेख करना चाहूँगा। हम सभी उन परिस्थितियों से अवगत हैं जिनके तहत एनबीएफसी-एफएमआई के लिए नियामक ढांचा तैयार किया गया था। तब से काफी समय बीत चुका। कई बड़े एमएफआई लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हो गए हैं। समग्र माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में एनबीएफसी-एमएफआई की हिस्सेदारी घटकर 30 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गई है। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ विनियामक कठोरता केवल माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के एक छोटे हिस्से पर लागू है। माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में विनियामक साधनों को फिर से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि हमारे नियम इकाई-आधारित होने के बजाय गतिविधि-आधारित हों। आखिरकार, माइक्रोफाइनेंस विनियमन का मूल ग्राहक / उपभोक्ता संरक्षण में निहित है।

हमें विनियमन की हद और लचीलेपन के बीच सही संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है - एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। एनबीएफसी के लिए संभवतः हम एक क्रमिक विनियामक ढाँचे पर विचार कर सकते हैं जो प्रणालीगत महत्ता में उनके योगदान के अनुसार निर्धारित हो।

### फिनटेक का विनियमन

अब मैं समकालीन रुचि के किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। यद्यपि फिनटेक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक कदम पहले ही उठाए गए हैं, लेकिन फिनटेक केंद्रित एनबीएफसी की गतिशील प्रकृति नई चुनौतियाँ लाती रहती है। एनबीएफसी क्षेत्र फिनटेक-प्रदत्त अभिनव उत्पादों और सेवाओं को अपनाने में सबसे आगे रहा है, जो इन सेवाओं की उपलब्धता और इनसे आदान-प्रदान के बारे में सोच को बदल रहे हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत तकनीकी समाधान को खिलाड़ी बड़ी संख्या में अपना रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशल तरीके से ऋण (क्रेडिट) उपलब्ध करा रहे हैं। नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास हेतु समर्थकारी परिवेश बनाने में रिजर्व बैंक सबसे आगे रहा है। वास्तव में, नॉन-बैंकिंग दुनिया में, रिजर्व बैंक औरों से आगे रहा है और उद्योग की शैशवावस्था

में ही उत्पादों और सेवाओं के नियम लेकर आया है। समकक्षी उधार (पीयर टू पीयर लेंडिंग), अकाउंट एग्रीगेटर और “केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म” पर ऋण मध्यस्थता इस संदर्भ के दृष्टांत हैं जहाँ नियमों ने उद्योग को व्यवस्थित और मजबूत तरीके से बढ़ने में मदद की है। फिनटेक क्षेत्र में भविष्य के नियम बनाते समय, व्यवस्थित वृद्धि व ग्राहक सुरक्षा और डेटा सुरक्षा रिजर्व बैंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बने रहेंगे।

### पारदर्शिता और अच्छा अभिशासन सुनिश्चित करना

अच्छा अभिशासन सुनिश्चित करना किसी भी विनियामक परिवर्तन का मूल है। यह उद्देश्य आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा अभिशासन तत्त्वतः एक आकांक्षामूलक उपलब्धि है और केवल विनियामकीय निर्देशों के आधार पर शायद ही इसे स्थापित किया जा सके। प्रमोटर/स्वामी व वरिष्ठ प्रबंधन यदि मूलतः ‘योग्य एवं उपयुक्त’ हों तो अच्छा अभिशासन उसकी स्वाभाविक परिणति होगी। ऐसी फिल्टरिंग व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है जो केवल खरे और सक्षम प्रमोटरों को ही एनबीएफसी का कारोबार शुरू करने दे। आखिर, नई एनबीएफसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जारी कर हम उन्हें जनता के पैसे तक पहुँचाने का अधिकार-पत्र देते हैं जो उनकी निवल मालियत का कई गुना होता है। साथ ही, यह आवश्यक है कि एनबीएफसी के रास्ते किसी भी तरह धन-शोधन और आतंक का वित्तपोषण न होने पाए। रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था में उपर्युक्त उद्देश्य पर उन कंपनियों के मामले में तो ध्यान दिया जाता है जो रजिस्ट्रेशन चाहती हैं, ऐसी ही सख्ती व अपेक्षित सावधानी उन मामलों में भी जरूरी है जब कभी मौजूदा एनबीएफसी के स्वामित्व/नियंत्रण में कोई परिवर्तन हो।

### उपभोक्ता संरक्षण व उचित आचरण

बैंक हो या एनबीएफसी, किसी भी विनियमित इकाई की सेवाओं का उपभोक्ता उचित व्यवहार एवं शिकायत निवारण के मार्गों के बारे में एक जैसी प्रत्याशा रखता है। लोकपाल योजना को बढ़ाकर एनबीएफसी क्षेत्र तक ले जाने का कदम इसी दिशा में है। भविष्य के लिए एक पारदर्शी व आत्मानुशासी तंत्र के बारे में सोचना होगा जहाँ करोबार के बदलते मॉडल और ऋण उपलब्ध

कराने की व्यवस्थाएं ग्राहक के प्रति उचित व्यवहार के मार्ग से विचलित न हों।

### निष्कर्ष

वैश्विक वित्तीय संकट का कारण मुख्यतः हल्के विनियामकीय दृष्टिकोण को माना गया था जिसमें अबाध वित्तीय नवाचार और वित्तीय मध्यस्थों द्वारा चलनिधि जोखिमों को अनदेखा किया गया। प्रचुर चलनिधि, हल्के विनियमन और वित्तीय नवाचार ने एनबीएफसी के बढ़ने में भी मदद की है। एक दशक से भी पहले वित्तीय संकट की शुरुआत की तुलना में आज की वित्तीय प्रणाली काफ़ी अलग है। उस संकट पर कार्रवाई के रूप में भारत में लागू किए गए विनियामक सुधार, तकनीक में परिवर्तन और, इससे भी अहम, एनबीएफसी के विकास ने इस गतिमान परिदृश्य में योगदान दिया है। एनबीएफसी क्षेत्र अत्यंत विविध हो गया है। एनबीएफसी की श्रेणी के अनुसार, कारोबार के मॉडल, ग्राहक व वित्तीय उत्पादों के स्वरूप में बहुत विभिन्नता होती है। विभिन्न एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की अंतर्निहित विविधता में इस क्षेत्र की विशिष्टता है और विनियामकीय कसौटी में सबके लिए एक ही मानदंड नहीं हो सकता। इकाइयों की प्रणालीगत

महत्ता के अनुपात में संभवतः एक नपा-तुला व क्रमिक विनियामक ढाँचा ही इसका उपाय है।

तकनीकी नवाचार तथा फिन-टेक के आधार पर वित्तीय सेवाओं व उत्पादों के दिए जाने से एक ओर जहाँ सामान्य जनता के लिए वित्तीय उत्पाद की बेहतर उपलब्धता का उद्देश्य आगे बढ़ता है, वहीं विनियामक पर यह दबाव पड़ता है कि विनियामकीय हस्तक्षेप का तदनुसार नपा-तुला पुनर्निर्धारण किया जाए ताकि उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य प्राप्त हो। इन पृथक व कभी-कभी विरोधी लक्ष्यों का तालमेल बिठाने में विनियामक के लिए चुनौतियां कई हैं, तथापि उद्देश्य की स्पष्टता सही नीतिगत निर्णय लेने में हमारी सहायता करेगी।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि महामारी के विरुद्ध इस लंबी लड़ाई में आप और आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। आपको खुशियों भरी और सुरक्षित दीपावली की भी शुभकामनाएं।

धन्यवाद।